FSSAI की राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अपील, मोटापे के खिलाफ पीएम के आह्वान पर करें अमल

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 28 मई 2025: माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मोटापे के खिलाफ कार्रवाई और तेल की खपत में 10% की कमी लाने के आह्वान पर, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती चिंता से निपटने के लिए जागरूकता प्रयासों को बढ़ाने और ठोस उपाय लागू करने का आग्रह किया। इस मामले पर 27 मई, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 47वीं केंद्रीय सलाहकार समिति (CAC) की बैठक के दौरान विचार-विमर्श किया गया।

विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रधान मंत्री के मोटापे-मुक्त और स्वस्थ राष्ट्र के आह्वान को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए व्यापक उपायों, जिसमें व्यापक जन जागरूकता अभियान शामिल हैं, को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का दृढ़ता से आग्रह किया गया।

बैठक के दौरान चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का स्कूलों में 'शुगर बोर्ड' स्थापित करने संबंधी हालिया निर्देश था। FSSAI ने राज्यों द्वारा इस महत्वपूर्ण पहल का सक्रिय रूप से समर्थन और बड़े पैमाने पर इसे लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि यह स्कूली बच्चों में अत्यधिक चीनी के सेवन को काफी हद तक कम करने और कम उम्र से ही स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगा।

FSSAI ने इस बात पर जोर दिया कि इन सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों के सफल निष्पादन के लिए राज्य महत्वपूर्ण हैं। चर्चाओं में राज्यों के लिए अपनी खाद्य सुरक्षा निगरानी बढ़ाने, 'ईट राइट इंडिया' आंदोलन को बढ़ावा देने और समाज के सभी वर्गों में पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य विकल्पों की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने की रणनीतियों पर विचार किया गया। प्राधिकरण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रयासों में सभी आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

47वीं सीएसी बैठक में खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों और खाद्य उद्योग, उपभोक्ता समूहों, कृषि, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संगठनों के हितधारकों सहित 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।